राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 5927/2024

अंकित कुमार पुत्र अविनाश कुमार, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 25, पावर हाउस के पास, बड़ोपाल रोड, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री बी.एस. संधू।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विजय राजपुरोहित, पी.पी.

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>29/08/2024</u>

1. याचिकाकर्ता अभियुक्त ने श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ पुलिस थाने में दर्ज आईपीसी की धारा 452, 323, 382, 147, 148 और 149 के तहत दिनांक

16.02.2023 की एफआईआर संख्या 51/2013 से उत्पन्न केस संख्या 146/2016 में विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ द्वारा पारित दिनांक 13.08.2024 के आदेश को रद्द करने की मांग की है। विवादित आदेश के तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने वाले आवेदन को खारिज कर दिया, याचिकाकर्ता अभियुक्त के जमानत बांड जब्त कर लिए और उसके जमानतदार के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 446 के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से रह रहा है और वहीं काम कर रहा है, और उसके लिए सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना संभव नहीं है। उनका तर्क है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में याचिकाकर्ता की स्थिति की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखा गया है और इसलिए, आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता कार्यवाही से भागने की कोशिश कर रहा है या ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहा है। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने वाले उसके आवेदन को खारिज करना, उसकी जमानत बांड जब्त करना और उसके जमानतदार के खिलाफ धारा 446 के तहत कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं था। इसलिए, विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

3. विद्वान लोक अभियोजक नीचे दिए गए कारणों से निचली अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश का समर्थन करेंगे।

4. कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में, मुझे मोहम्मद हरास बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य: सीआरएम-एम संख्या 31385/2023, दिनांक 07.07.2023 को तय

मामले में निर्णय देने का अवसर मिला, जिसका प्रासंगिक विवरण, तत्काल संदर्भ के लिए, नीचे दिया गया है:

"5. सुना गया।

6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट को जमानत रद्द करने का विवेकाधिकार है, हालांकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस तरह के आदेश पारित करने से पहले, कोर्ट को आरोपी को नोटिस जारी करना आवश्यक है ताकि उसे यह बताने का अवसर मिले कि जमानत क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में संगरूर के विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने ऐसा तरीका नहीं अपनाया है। केवल इसी आधार पर, जमानत रद्द करने की सीमा तक आरोपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

7. इसके अलावा, जमानत रद्द करना एक गंभीर मामला है और किसी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों को इस तरह से हल्के में और इस तरह से यांत्रिक तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए जैसा कि इस मामले में है।

8. इस आधार पर, आरोपित आदेश को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष पहले से प्रस्तुत जमानत बांड और जमानत बांड पर पहले से ही जमानत आदेश को पुनर्जीवित किया जाता है। याचिकाकर्ता को आज से तीन सप्ताह के भीतर विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है और बिना किसी देरी के विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होना जारी रखेगा।

9. तदनुसार याचिका स्वीकार की जाती है।"

5. याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है। धारा 446 सीआरपीसी के तहत जमानतदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संबंध में, यह भी विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा की गई एक गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटि है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। संयोग से, इस बिंदु पर भी, जब मैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश था, तो मुझे वरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य: (2023: पीएचएचसी: 104379) नामक एक मामले में निर्णय देने का अवसर मिला, जिसके लिए प्रासंगिक, तत्काल संदर्भ के लिए, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "9. संहिता की धारा 444 और 446 के वैधानिक प्रावधानों और ऊपर दर्ज टिप्पणियों के आलोक में, मेरी राय है कि जमानतदार को मुक्त करने और जब आवश्यक हो, बांड जब्त करने और जमानतदार पर जुर्माना लगाने के लिए उठाए जाने वाले आगे के कदमों को नियंत्रित करने वाली निम्नलिखित प्रक्रिया और सिद्धांतों को अदालतों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए:
>
> ए. ए.1. जमानतदार को मुक्त करना जमानतदार किसी भी स्तर पर मुक्ति की मांग कर सकता है: एक व्यक्ति जो जमानत पर रिहा हुए किसी व्यक्ति के लिए जमानतदार है, उसे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए अदालत में आवेदन करने का अधिकार है। वह बांड से पूरी तरह से मुक्ति की मांग कर सकता है।

ए.2. अभियुक्त के लिए गिरफ्तारी का वारंट: जमानतदार से आवेदन प्राप्त होने पर, अदालत संबंधित व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगी जिसे जमानत पर रिहा किया गया था ताकि उसे अदालत के समक्ष पेश किया जा सके।

ए.3 जमानत पर रिहा हुए व्यक्ति की उपस्थिति: एक बार व्यक्ति को जमानत पर रिहा किए जाने के बाद, अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट के माध्यम से न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या अन्यथा उपस्थित होता है, तो न्यायालय जमानत बांड को समाप्त करने का निर्देश देगा।

ए.4. नए जमानतदारों की खोज: एक बार न्यायालय द्वारा जमानत के लिए बांड के समाप्त करने का आदेश दिए जाने के बाद, जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को अन्य पर्याप्त जमानतदार खोजने की आवश्यकता होगी।

ए.5. विफलता के परिणाम: यदि जमानत पर रिहा किया गया व्यक्ति आवश्यकतानुसार अन्य पर्याप्त जमानतदार खोजने में विफल रहता है, तो न्यायालय उसे जेल भेज सकता है।

बी. जमानत बांड जब्त करने और जुर्माना लगाने के लिए बी.1 बांड और सबूत की जब्ती:- यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने या संपत्ति पेश करने के लिए बांड निष्पादित किया जाता है और न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित हो जाता है कि बांड जब्त कर लिया गया है, तो न्यायालय को ऐसे सबूत के लिए आधार दर्ज करना चाहिए। इसी तरह, यदि

किसी अन्य संदर्भ में बांड जब्त किया जाता है, तो न्यायालय को जब्ती के लिए आधार भी दर्ज करना चाहिए।

बी.2. नोटिस और जुर्माना:- तब न्यायालय उस व्यक्ति को जो बांड से बंधा हुआ है (जमानतदार) बुला सकता है कि वह बांड में निर्दिष्ट जुर्माना अदा करे या कारण बताए कि जुर्माना क्यों नहीं अदा किया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त कारण नहीं दिखाया जाता है और जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो न्यायालय जुर्माना लगाने के लिए कार्रवाई कर सकता है।

बी.3 विवेकाधीन छूट:- न्यायालय के पास जुर्माने के एक हिस्से को माफ (कम) करने और केवल शेष राशि के लिए भुगतान लागू करने का विवेकाधिकार है, जिसका अर्थ है कि बांड को जब्त करना अपने आप में जुर्माना लगाने के बराबर है और जुर्माना लगाने के लिए एक विशिष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए।

बी.4 जुर्माना अदा न करने पर दीवानी कारावास यदि लगाया गया जुर्माना अदा नहीं किया जाता है या वसूल नहीं किया जा सकता है, तो जमानतदार को छह महीने तक की अवधि के लिए दीवानी जेल में कारावास हो सकता है।

बी.5. जमानतदार की मृत्यु:- यदि बांड जब्त होने से पहले बांड का जमानतदार मर जाता है, तो उसकी संपत्ति बांड से संबंधित किसी भी दायित्व से मुक्त हो जाती है।

बी.6. दोषसिद्धि का साक्ष्य के रूप में उपयोग:- यदि कोई व्यक्ति जिसने धारा 106 या धारा 11 या धारा 360 के तहत सुरक्षा प्रदान की है, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिसके किए जाने से उसके बांड की शर्तों का उल्लंघन होता है या धारा 448 के तहत उसके बांड के बदले में निष्पादित बांड (नाबालिग के लिए) का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति को जमानतदार के खिलाफ साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध उसी व्यक्ति द्वारा किया गया था, जब तक कि इसके विपरीत साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए जाते।"

6. उपर्युक्त दो निर्णयों के आलोक में, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता अभियुक्त के जमानत-बंधपत्रों को जब्त करने और उसके जमानतदार के खिलाफ धारा 446 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने वाले आक्षेपित आदेश को अनिवार्य रूप से रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है।

7. परिणामस्वरूप, दिनांक 13.08.2024 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता-अभियुक्त के मूल जमानत-बंधपत्रों के साथ-साथ उसके जमानतदार के बांडों को बहाल किया जाता है और कानून के अनुसार आगे की सुनवाई की जाती है।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया का स्थायी निवासी है और यदि वह व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए आवेदन करता है, तो विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा उस पर उचित तरीके से विचार किया जाएगा और उसे राजस्थान उच्च न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम,

2021 के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जा सकती है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।